प्रदेश की दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हुआ है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प यात्रा अभियान को संबोधित किया व बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन किए

जैतारण/जयपुर, 23 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए ऐसा रोडमैप तैयार किया है, जिससे प्रदेश के हर गांव का सुनियोजित विकास होगा। इसमें खेल मैदान से लेकर अटल ज्ञान केन्द्रों की सुविधाएं शामिल हैं। हमारी सरकार की मंशा है कि युवा इन अटल ज्ञान केन्द्रों में ई-लर्निंग की सुविधाओं का फायदा उठाएं और भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।

मुख्यमंत्री बुधवार को जैतारण में सेवा संवाद कार्यक्रम-सेवा संकल्प यात्रा अभियान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हुआ है। राजस्थान की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रामजल सेतु, यमुना जल समझौता, नर्मदा समझौता और किशाऊ बहुद्देश्यीय बांध परियोजना जैसे बड़े अंतरराज्यीय समझौते हुए हैं।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास का ऐसा रोड मैप तैयार किया है, जिससे प्रदेश के हर गाँव का सुनियोजित विकास होगा।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जैतारण में सेवा संवाद कार्यक्रम-सेवा संकल्प यात्रा अभियान को संबोधित किया। इस अवसर पर आमजन व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक एवं ट्राई साइकिल वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधारोपण भी किया। साथ ही, उन्होंने पावन धाम परिसर में जैन संत रूपमुनि महाराज एवं मिश्रीमल महाराज के समाधि स्थल पर नमन किया।

बुधवार को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा रामदेव मंदिर में पावन समाधि के दर्शन किए एवं पूजा-अर्चना की तथा मंदिर परिसर में ही डालीबाई की समाधि के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने जम्मा-जागरण स्थल पर बाबा रामदेव की रिक्खियों का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री ने नि:शुल्क भोजनशाला में श्रद्धालुओं को प्रसादी परोसी। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने बस स्टैण्ड से पदयात्रा प्रारंभ की तथा मुख्य बाजार से होते हुए मंदिर तक पहुंचे। पद यात्रा में मुख्यमंत्री बाबा रामदेव की ध्वजा (नेजा) थामे हुए थे। मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने रामदेवरा के मुख्य बाजार में जनप्रतिनिधियों के साथ चाय पी तथा आमजन से बातचीत की।

'महिलाओं की सुरक्षा का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "बड़ी जिम्मेदारी यह है कि माहौल को ही अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बनाया जाए।" ज्ञातव्य है कि सोमवार शाम एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में बलात्कार किया था। यह पार्क कॉलेज परिसर से करीब दो किलोमीटर दूर है। एलएसआर की प्रिंसिपल कनिका के आहूजा ने कहा, "दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलने के बाद हमने कक्षाएं रद्द कर दीं। हमारी छात्राओं की सुरक्षा, संरक्षा और उनका कल्याण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।" कॉलेज ने अमर कॉलोनी पुलिस थाने से भी कहा है कि वह परिसर से जुड़ी गलियों में गश्त बढ़ाये, खासकर पिछले गेट और आसपास के पार्कों के पास। कॉलेज ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के लगातार संपर्क में है और परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। फैकल्टी मैन्टॉर्स (मार्गदर्शक शिक्षक) और कॉलेज के काउंसलर से भी कहा गया है कि जिन छात्राओं को सहायता की जरूरत हो, उनके लिए वे उपलब्ध रहें।

ट्रंप प्रोटोकॉल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी विश्व नेता का बेस पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेगा।

इससे पहले 1962 में जॉन एफ. कैनेडी ने टारमैक पर यूके के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन का स्वागत किया था।

फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि यह कदम शी के प्रति ट्रंप के गहरे सम्मान को प्रदर्शित करेगा।

"ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करें व पुरानी मतदान सूची से फिर विधानसभा चुनाव करायें"

कोलकाता, 23 सितंबर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तत्काल गिरफ्तारी और राज्य में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) से पहले वाली मतदाता सूची के आधार पर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है।

फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक पद उनके जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है।

मायावती ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में बीएसपी की ऑल-इंडिया स्तर की विशेष बैठक की। बैठक में इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बसपा द्वारा अकेले लड़ने की तैयारियों और उम्मीदवार चयन को लेकर पिछले दिशा-निर्देशों के अमल की समीक्षा की गई।

निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति बड़ी बैंच को भेजने पर एकमत नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के जज

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहते हैं, पर जस्टिस दत्ता इसके खिलाफ हैं

- **पिछली सुनवाई में केन्द्र सरकार ने मामले को संविधान बैंच को भेजने की मांग की थी और 30 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था।**

नई दिल्ली, 23 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बड़ी बेंच के पास भेजने के मुद्दे पर दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है और इस पर दो जजों की बेंच ही फैसला कर सकती है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के पक्ष में फैसला दिया।

उच्चतम न्यायालय ने 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान, केन्द्र सरकार ने इस मामले को संविधान बेंच को भेजने की मांग की थी। केन्द्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में बड़ी बेंच के फैसले की जरुरत है। इस मामले में एडीआर के अलावा एक याचिका जया ठाकुर ने दायर की थी। याचिका में चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को भी रखने की मांग की गई थी। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों ने भी याचिका दायर कर रखी थी। याचिका में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना जरुरी है।

'बिना सुनवाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्रवाई को अवैध घोषित किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जेडीए के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

'राजनैतिक दुष्प्रचार को बार-बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के समर्थन को भी दोहराया गया।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत तथाकथित ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की जम्मू-कश्मीर पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भारत के संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, जो अनावश्यक और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ओआईसी को उन मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो पूरी तरह भारत के आंतरिक मामले हैं।" मंत्रालय ने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केन्द्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और राजनीतिक रूप से प्रेरित दुष्प्रचार को बार-बार दोहराने से यह वास्तविकता बदल नहीं सकती। इस तरह के प्रेरित आख्यानों का बार-बार समर्थन करना ओआईसी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मंत्रालय ने ओआईसी को सलाह दी कि वह पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर ध्यान केन्द्रित करे, न कि उसके दावों को बढ़ावा दे। बयान में कहा गया, "पाकिस्तान को उसके मनगढ़ंत और प्रेरित दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए मंच उपलब्ध कराने के बजाय, ओआईसी के लिए बेहतर होगा कि वह पाकिस्तान, जिसका आतंकवाद का समर्थन और प्रायोजन करने का एक अच्छा-खासा दस्तावेजीकृत रिकॉर्ड है, को सलाह दे कि वह आत्मनिरीक्षण करे और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों से लगातार उत्पन्न हो रहे आतंकवाद के खतरे से निपटे।

पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने ओआईसी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर एकजुट रुख बनाए रखें। डार ने भारतीय प्रशासन वाले जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और नागरिक गतिविधियों के लिए जारी प्रतिबंधों का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसके जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य विवाद बना हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी घरेलू उपाय संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का स्थान नहीं ले सकता। डार ने मई 2025 के संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि यह संघर्ष विवाद को अनसुलझा छोड़ने के खतरों की याद दिलाता है।

भारत की इस प्रतिक्रिया से एक दिन पहले तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, "दक्षिण एशिया में यह महत्वपूर्ण है कि कश्मीर मुद्दे सहित, सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में की गई उनकी टिप्पणी में यह उदाहरण भी दिया गया कि भारत की लगातार आपत्तियों के बावजूद, अंकारा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे को उठाया है।

नितिन नबीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभियान का शुभारम्भ करेंगे। वे यहाँ से 90 प्रचार रथों को रवाना करेंगे।

नितिन नबीन दोपहर 2.30 बजे बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यु सर्किल जयपुर में "युवा संवाद" कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने विचार साझा करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रमों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार सहित, प्रदेश के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे।

गौतम अडाणी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग आधे के बराबर है। देश में पिछले पांच वर्षों में डॉलर अरबपतियों की संख्या 237 से बढ़ कर 391 हो गई है, जिसमें अकेले पिछले एक साल में 27 नए डॉलर अरबपति जुड़े हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908